

**मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को
अखिल भारतीय परमिट**

***357. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :**
क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने
की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय
द्वारा स्वतंत्रियोजन योजना के अन्तर्गत मध्य
प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को यात्री
बसों तथा ट्रकों के लिए पिछले तीन वर्षों
के दौरान कितने अखिल भारतीय परमिट
जारी किये गये हैं; और

(ख) उन व्यक्तियों के नाम तथा
पते क्या हैं तथा ये परमिट किस वर्ष से
जारी किए गए हैं ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND
TRANSPORT (SHRI K. VIJAYA BHAS-
KARA REDDY): (a) and (b) The Min-
istry of Shipping & Transport does not
issue any kind of permits. It only specifies
the number of permits which may be
issued by the respective State Govern-
ments. Hence no record of allottees is
maintained in the Ministry.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : समापति
जी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वे
जो परमिट जारी करते हैं उनका रिकार्ड
भी नहीं रखते हैं और परमिट जारी भी नहीं
करते हैं, लेकिन संख्या निर्दिष्ट करते हैं तो
में पूछना चाहता हूँ कि पिछले तीन वर्षों
में मैंने मध्य प्रदेश के विषय पूछा है कितने
परमिट देने के लिए कितनी संख्या में ट्रक और
बसेज के परमिट देने के बारे में आपने प्रदेश
सरकार को कहा है, कितनी संख्या में ?
वस और ट्रक का अलग अलग तीन वर्षों का
ब्योरा दें।

SHRI K. VIJAYA BHASKARA
REDDY: Sir, I have figures for 1981-82.

MR. CHAIRMAN: Separately for buses
and trucks.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA RED-
DY: Figures for one year are available
with me. For other years, figures are not

available. I can send to the hon. Member.
In 1982, 1350 national permits for public
carriers were specified for issue for the
State of Madhya Pradesh (Inter-
ruptions)

MR. CHAIRMAN: May I request you
to read it again, because the hon. Mem-
ber was not anxious to hear?

SHRI K. VIJAYA BHASKARA RED-
DY: Sir, in 1982, 1350 national permits
for public carriers were specified for issue
for the State of Madhya Pradesh. As per
the information available, 760 national
permits have been issued for various cate-
gories. I have got the figures for 1982.
Other figures I have not got.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मैंने तीन
वर्ष के मांगे थे, दो वर्ष के परमिट की संख्या
बाद में देंगे यह आश्वासन मिलना चाहिए।
उन्होंने एक वर्ष का दिया है।

श्री समापति : अभी आपको मंगवाकर
दे देंगे।

• SHRI K. VIJAYA BHASKARA RED-
DY: I will examine.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मेरा दूसरा
सवाल यह है कि जितनी संख्या में परमिट
देने का निर्देश आपने मध्य प्रदेश सरकार
को दिया है, मैं जानना हूँ कि उसमें से कितने
परमिट शिक्षित बेरोजगारों को दिए गए हैं ?

श्री समापति : ये फिगर आपके पास हैं ?

SHRI K. VIJAYA BHASKARA RED-
DY: Sir, there is no restriction that way.
The State Government has certain rules
and we have also given certain directions.
This specific thing is not there in the Act.
It is for the State authorities to decide and
act.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : एक मिनट
मेरी बात सुन लें। बात ठीक नहीं हो रही
है। केन्द्रीय सरकार का यह नियम है कि
वह बेरोजगारों के रोजगार के लिए हर
बात में कोई न कोई सुविधा देती है।

मेरा निवेदन यह है कि परमिटों के बारे में भी केन्द्रीय सरकार का यह निर्देश है। इसलिए बस और ट्रक्स के परमिटों के बारे में केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश सरकार को यह निर्देश क्यों नहीं दिया कि उनको निश्चित संख्या में परमिट दें? यह निर्देश क्यों नहीं दिया गया? यह होना चाहिए और इस बारे में मंत्री जी जरूर कहें।

श्री समापति : आप बैठिए। उनको इंतज़ार ही नहीं हो रहा है।

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: This is for the State Government to decide.

श्री समापति : स्टेट गवर्नमेंट सबजेक्ट यहाँ लेकर के बैठे हैं।

श्री बुद्ध प्रिय सोर्य : माननीय समापति जी, कल भी यह प्रश्न आया था और उत्तर में सरकार ने यह माना था कि शैड्यूल कास्ट्स और शैड्यूल ट्राइब्स के लोगों की संख्या गरीबों की रेखा के नीचे और दूसरे लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो शैड्यूल कास्ट्स और शैड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए...

श्री समापति : कोई बात इंतज़ार मत।

श्री बुद्ध प्रिय सोर्य : ... देश की इकतानमी की मेनस्ट्रीम में उनको लाया जा सके और वह गरीबों और पिछड़ेपन से अपना पीछा छुड़ा सके। क्या ऐसी व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने की है कि उनको कम से कम 33 प्रतिशत सुरक्षित परमिट उनके लिए रहें, ताकि वह भी भारत के आर्थिक विकास का आनन्द ले सकें और उसमें भागीदार बन सकें?

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, there is no reservation that way. Again I repeat, it is for the State Government, the State transport authorities, to fix these things. In the Act, Centre has not been given anything.

MR. CHAIRMAN; I think we will finish it with this now.

डा० भाई महावीर : श्रीमान्, क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि प्रायः शिक्षित बेरोजगारों के लिए जिन सुविधाओं का आश्वासन दिया जाता है, वे सुविधाएं कागज पर तो भले ही सुलभ हों; व्यवहार में उनको प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। शिक्षित इंजीनियरों को अपना रोजगार या कामकाज स्थापित करने के लिए कोई आश्वासन दिये गये थे पर मैं ऐसे उदाहरण जानता हूँ कि तीन-तीन वर्ष तक उनको एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर और दूसरे से तीसरे और चौथे दफ्तर तक भटकना पड़ता है इसके पहले कि वे अपना काम शुरू कर सकें।

तो इस विणिष्ट सन्दर्भ में क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो शिक्षित बेरोजगार परमिट प्राप्त करेंगे, उस परमिटों का उपयोग करके वे कुछ काम में ला सकें, इसके लिए भी उन्हें समय पर सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है या खाली एक कागज पकड़ा कर उन्हें घर भेज दिया गया है?

श्री समापति : कागज पकड़ा कर डिग्री तो यूनिवर्सिटी भी दे देती है और घर भेज देती है।

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, again I will have to repeat that it is the State Government that has to formulate all these things.

MR. CHAIRMAN; The point is, what the employment openings are for these people and whether there is any effort made.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, the State Governments are making their own efforts, and the Madhya Pradesh Government also may be making efforts. We have asked for some information, the list and all that, from the Madhya Pradesh Government. We have not got it.

DR. BHAI MAHAVIR; It is a question of all-India permits, and I suppose

where Central areas are concerned, as for example in Delhi, they must be having some norms which are applicable to States as well as to Central territories, i.e. for person is given permits in a Central territory. Do they have any such arrangements which would correspond to similar arrangements in a State?

श्री समापति : उसमें चाहते क्या हैं कि उनको परमिट के साथ एक बस भी दे दी जाए।

डा० भाई महावीर : नहीं, साहब कागज पर तो वे सवारी नहीं कर सकेंगे और न वे कागज को चला कर रोजगार ही कमा सकते हैं।

श्री समापति : यह तो रोज हो रहा है, 21 हजार डिग्रियां मिल जाती हैं और उनको कागज पकड़ा देते हैं, नौकरी नहीं मिलती।

डा० भाई महावीर : इसीलिए, महोदय, ये डिग्री के जैसे ही हैं—जहां पर परमिट की व्यवस्था की जाती है वहां जरूरी है वे उस परमिट से रोजगार कमाने लायक हो सकें। अगर वे रोजगार कमाने लायक हो सकें, तो वे उसे बेच देंगे और एक तरह का बेनामी बिजनेस शुरू हो जाएगा।

श्री समापति : यह अन्फाबुटिली सिटुएशन है कि जो ट्रेनिंग पाते हैं, उनके लिए ओपनिंग नहीं रहती। अगर आप उसमें जरा नम्बर दर्ज कर दें... (व्यवधान)

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, यही समस्या है कि सुविधा तो आप दें और वह सुविधा बेनामी तरीके से या तो विक्रि जाए या किराए पर उसको लेकर कोई दूसरा इस्तेमाल करे, क्या इस तरह से इस योजना का पर्पज पूरा हो जाएगा ?

श्री समापति : मालूम नहीं। क्या डाइविंग लाइसेंस विक्रि होते हैं ? अब तो तस्वीर लगती है।

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Here and there certain misuse of these permits has come to our notice. We have directed the States to take action. It is for the State Governments essentially to implement this.

DR. BHAI MAHAVIR: I am sorry, Sir, He is not appreciating my point. It is not a question of misuse.

श्री समापति : माफ़ करिये, आप के सवाल का जवाब हो गया। मिस्टर कुलकर्णी।

SHRI A. G. KULKARNI: May I know from the hon. Minister whether his Ministry has received complaints from various State Governments, including Madhya Pradesh, that the issue of national permits is overlapping the routes undertaken by the State Road Transport Corporations and thereby the earnings or profits of the State Road Transport Corporations are always suffering? Has the Minister received any such complaint? Or, does he know whether there is such a genuine complaint? If so, what steps are envisaged?

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, I have no specific information about any particular State. Here and there we have received certain things. Periodically our officers meet and discuss and solve that type of problems. I do not have information about any specific State. I can send it to the Member.

MR. CHAIRMAN: Question No. 358.

Central Aid for voluntary Organisations in Andhra Pradesh

*358, **SHRI V. C. KESAVA RAO:** Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) what was the amount given to the Government of Andhra Pradesh for disbursing to voluntary organisations which are running a number of children homes and orphanages;